

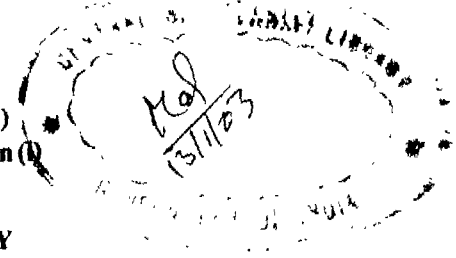


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2002/ज्येष्ठ 21, 1924

No. 268]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2002/JYAISTHA 21, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2002

सं. 34/02 एन.टी.-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 420(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) का धारा 8ग का उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियम, 2002 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) "समालोचनात्मक परिस्थितियों" से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं जिनमें इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि आयात ऐसी वर्धित मात्राओं में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन किए गए हैं कि जिससे घरेलू उद्योग के लिए बाजार विच्छिन्नता कारित होती है या कारित होने की आशंका है और अनन्तिम सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण में विलम्ब घरेलू उद्योग के लिए अपूरणीय नुकसान कारित करेगा।

(ग) "वर्धित मात्रा" के अन्तर्गत आयातों में वृद्धि है, जो चाहे आत्यन्तिक निबंधनों में हो या घरेलू उद्योग की अनुपाती।

(घ) "हितबद्ध पक्षकार" के अन्तर्गत निम्नलिखित है,—

(i) किसी ऐसी वस्तु का कोई निर्यातकर्ता या विदेशी उत्पादक या आयातकर्ता जो अधिनियम की धारा 8ग के अधीन सुरक्षा शुल्क अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण के अध्यधीन की गई है, या कोई ऐसा व्यापार या कारबार मंगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य ऐसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हैं;

(ii) चीन जनवादी गणराज्य की सरकार; और

- (iii) भारत में वैसी ही वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतियोगी वस्तु का कोई उत्पादक या कोई व्यापार या कारखाना संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य भारत में वैसी ही वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतियोगी वस्तु का उत्पादन या व्यापार करते हैं;
- (ड) "वैसी ही वस्तु" से ऐसी कोई वस्तु अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 8ग के अधीन अन्वेषणाधीन वस्तु के सभी प्रकार से तदरूप या समान है;
- (घ) "अनन्तिम शुल्क" से अधिनियम की धारा 8ग की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित सुरक्षा शुल्क अभिप्रेत है;
- (छ) ऐसे सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वहाँ अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनको क्रमशः दिए गए हैं।

3. महानिदेशक (विनिर्दिष्ट सुरक्षा) की नियुक्ति :—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का नहीं या ऐसे अधिकारी जिसे वह ठीक समझे, महानिदेशक (विनिर्दिष्ट सुरक्षा) नियुक्त कर सकेगी, जिसे इससे इसमें पश्चात् इन नियमों के प्रयोजनों के लिए महानिदेशक कहा गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार, महानिदेशक को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे।

4. महानिदेशक के कर्तव्य :—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, महानिदेशक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

- (1) भारत में किसी वस्तु के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" की विद्यमानता का अन्वेषण करना;
- (2) अधिनियम की धारा 8ग के अधीन सुरक्षा शुल्क के लिए दायी वस्तु की पहचान करना;
- (3) चीन जनवादी गणराज्य से किसी वस्तु के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" की विद्यमानता के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने अन्तिम या अन्यथा निष्कर्ष प्रस्तुत करना;
- (4) निम्नलिखित की सिफारिश करना—
 - (i) शुल्क की ऐसी रकम, जो यदि उद्ग्रहीत की जाती हो तो घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी;
 - (ii) अधिनियम की धारा 8ग के अधीन सुरक्षा शुल्क के उद्ग्रहण की कालावधि।
- (5) ऐसी सुरक्षा शुल्क के जारी रखे जाने की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करना।

5. अन्वेषण का प्रारंभ :—उपनियम (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, महानिदेशक वैसी ही वस्तु या प्रत्यक्षतः प्रतियोगी वस्तु के घरेलू उत्पादक द्वारा या उसकी ओर से किसी लिखित आवेदन की प्राप्ति पर घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" का, जो किसी वस्तु के ऐसी वर्धित मात्रा में, जो चाहे आत्यन्तिक हो या घरेलू उद्योग की अनुपाती, आयात द्वारा कारित हो, अवधारण करने के लिए अन्वेषण प्रारंभ करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन उस प्ररूप में होगा जो इस निमित्त महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसा आवेदन,—

- (i) वर्धित आयात;
- (ii) घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" या बाजार विच्छिन्नता की आशंका; और
- (iii) आयात और अभिकथित "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" के बीच आकस्मिक संबंध के साक्ष्य द्वारा अनुसमर्थित होगा।

(3) महानिदेशक उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के अनुसरण में अन्वेषण तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक कि वह आवेदन में दिए गए साक्ष्य की यथार्थता और पर्याप्तता की जांच पड़ताल नहीं कर लेता है और उस का यह समाधान नहीं हो जाता है कि,—

- (क) वर्धित आयात;
- (ख) "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका"; और
- (ग) वर्धित आयात और अभिकथित "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" के बीच आकस्मिक संबंध के विषय में पर्याप्त साक्ष्य है।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक कोई अन्वेषण स्वप्रेरणा से शुरू कर सकेगा यदि उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त किसी सीमाशुल्क आयुक्त से, या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी से यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है।

6. अन्वेषण को शासित करने वाले सिद्धान्त—(1) महानिदेशक, भारत में किसी वस्तु के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की “बाजार विच्छिन्नता” या “बाजार विच्छिन्नता की आशंका” को अवधारित करने के लिए अन्वेषण शुरू करने का विनिश्चय करने के पश्चात् अपना यह विनिश्चय अधिसूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा। सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी, अर्थात् :—

- (i) अन्तर्वर्तित वस्तु;
- (ii) अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख;
- (iii) ऐसे तथ्यों का संक्षिप्त विवरण जिन पर “बाजार विच्छिन्नता” या “बाजार विच्छिन्नता की आशंका” का अभिकथन आधारित है;
- (iv) अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए कारण;
- (v) वह पता जिस पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन भेजे जाने चाहिए; और
- (vi) हितबद्ध पक्षकारों को उनके अभिगत ज्ञात कराने के लिए अनुज्ञात समय-सीमा।

(2) सार्वजनिक सूचना की एक प्रति महानिदेशक द्वारा केंद्रीय सरकार के वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय को और अन्य संबंधित मंत्रालयों को, ऐसी वस्तु जिसके वर्धित आयात से घरेलू उद्योग की “बाजार विच्छिन्नता” कारित हुई है या के ज्ञात निर्यातकर्ताओं को, कारित होने की आशंका अभिकथित की गई है, चीन जनवादी गणराज्य की सरकार की ओर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की जाएगी;

(3) महानिदेशक नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति—

- (i) ज्ञात निर्यातकर्ताओं या संबद्ध व्यापार संगम,
- (ii) चीन जनवादी गणराज्य की सरकार, और
- (iii) केंद्रीय सरकार के वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय,

परन्तु महानिदेशक को भी उपलब्ध कराएगा। आवेदन की एक प्रति, लिखित अनुरोध पर, किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को भी उपलब्ध कराएगा।

(4) महानिदेशक, निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों और चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के ऐसे प्रकरों में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कोई जानकारी मंगाने के लिए सूचनाएं जारी कर सकेगा और ऐसी जानकारी उनके द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, महानिदेशक अनुज्ञात करे, लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेज उस तारीख से, जिसको ये दस्तावेज महानिदेशक द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के समुचित राजनयिक प्रतिनिधि को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए थे या संप्रेषित किए गए थे, एक सप्ताह के पश्चात् प्राप्त हो गए समझे जाएंगे।

(5) महानिदेशक अन्वेषणाधीन वस्तु के औद्योगिक उपभोक्ता को और इस दशा में जहां वस्तु का सामान्य रूप से फुटकर स्तर पर विक्रय किया जाता है वहां प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी ऐसी जानकारी देने का अवसर प्रदान करेगा जो अन्वेषण के लिए सुसंगत हैं।

(6) महानिदेशक किसी हितबद्ध पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को अन्वेषण के लिए सुसंगत जानकारी मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु ऐसी मौखिक जानकारी पर महानिदेशक केवल तब ही विचार करेगा जब वह तत्पश्चात् लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है।

(7) महानिदेशक एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अन्वेषण में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा।

(8) उस मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार व्यक्तिगत कालावधि के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंचने देने से इन्कार करता है, या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या अन्वेषण में अत्यधिक अड़चन डालता है, वहां महानिदेशक उसको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और केंद्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा जिन्हें वह ऐसी परिस्थितियों में ठीक समझे।

7. गोपनीय जानकारी :—(1) नियम 6 के उपनियम (1), (3), और (7), नियम 9 के उपनियम (2) और नियम 11 के उपनियम (5) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है या जो गोपनीय आधार पर दी गई है, कारण दर्शित करने पर, महानिदेशक द्वारा उसी प्रकार की मानी जाएगी और उसे ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा।

(2) महानिदेशक गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी जानकारी देने वाले किसी पक्षकार की राय में, ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बताया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार महानिदेशक को ऐसे कारणों का एक कथन प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका संक्षेप तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या जानकारी देने वाला जानकारी को सार्वजनिक करने या साधारण या संक्षिप्त रूप में उसका प्रकटन प्राधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की तब तक अवहेलना कर सकेगा जब तक कि समुचित स्रोतों से उसके समाधानप्रद रूप में यह प्रदर्शन नहीं किया जाता है कि ऐसी जानकारी सही है।

8. "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" का अवधारण—महानिदेशक घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" का अवधारण, अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के उपाबंध में अधिकथित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए करेगा।

9. प्रारंभिक निष्कर्ष—(1) महानिदेशक शीघ्रता से अन्वेषण के संचालन के लिए अग्रसर होगा और समालोचनात्मक परिस्थितियों में "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" के विषय में प्रारंभिक निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(2) महानिदेशक अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(3) महानिदेशक सार्वजनिक सूचना की एक प्रति केंद्रीय सरकार के वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय को और वित्त से संबंधित मंत्रालय को भेजेगा।

10. अन्तिम शुल्क का उद्ग्रहण—केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 8ग की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, महानिदेशक के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, अन्तिम शुल्क अधिरोपित कर सकेगी :

परन्तु ऐसा शुल्क उस तारीख से, जिसको यह अधिरोपित किया गया या ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, जो दो सौ दिन से अधिक न हो।

11. अंतिम निष्कर्ष—(1) महानिदेशक, अन्वेषण प्रारंभ करने की तारीख से 8 मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, यह अवधारित करेगा कि—

(क) क्या अधिनियम की धारा 8ग के अधीन अन्वेषण के अधीन वस्तु के वर्धित आयात से घरेलू उद्योग को "बाजार विच्छिन्नता" कारित हुई है या कारित होने की आशंका है, और

(ख) क्या वर्धित आयात और "बाजार विच्छिन्नता" या "बाजार विच्छिन्नता की आशंका" के बीच आकस्मिक संबंध है ?

(2) महानिदेशक शुल्क की ऐसी रकम के बारे में भी जो, यदि उद्गृहीत की जाती है तो "बाजार विच्छिन्नता" को रोकने या उसके उपचार करने के लिए पर्याप्त होगी, अपनी सिफारिश देगा।

(3) महानिदेशक शुल्क के उद्ग्रहण की कालावधि के बारे में भी अपनी सिफारिश देगा।

(4) अन्तिम निष्कर्षों में, यदि वे सकारात्मक हैं तो, तथ्यों और विधि और उन कारणों के, जिनसे निष्कर्ष पर पहुंचा गया है, बारे में सभी जानकारी अन्तर्विष्ट होगी।

(5) महानिदेशक अपने अन्तिम निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(6) महानिदेशक अपने अन्तिम निष्कर्षों के बारे में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति केंद्रीय सरकार के वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय को और वित्त से संबंधित मंत्रालय को भेजेगा।

12. शुल्क का उद्ग्रहण—(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्तिम निष्कर्षों से समाविष्ट वस्तु के भारत में आयात पर, अधिनियम की धारा 8ग के अधीन ऐसा सुरक्षा शुल्क, जो "बाजार विच्छिन्नता" को रोकने या उसका उपचार करने के लिए पर्याप्त पाया गया है, अधिरोपित कर सकेगी।

(2) यदि महानिदेशक का अन्तिम निष्कर्ष नकारात्मक है अर्थात् उस प्रथम दृष्टया साक्ष्य के प्रतिकूल है, जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 8ग के अधीन अन्वेषण प्रारंभ किया गया था तो केंद्रीय सरकार नियम 11 के अधीन महानिदेशक द्वारा अन्तिम निष्कर्षों के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर अधिनियम की धारा 8ग के अधीन अधिरोपित अन्तिम शुल्क को, यदि कोई हो, वापस ले लेगी।

13. अविभेदकारी आधार पर शुल्क का अधिरोपण—अधिनियम की धारा 8ग के अधीन कोई भी सुरक्षा शुल्क, जो नियम 10 या नियम 12 के अधीन अधिरोपित किया गया हो अविभेदकारी आधार पर होगा और खीन जनवादी गणराज्य से ऐसी वस्तु के सभी आयातों को लागू होगा।

14. शुल्क के प्रारंभ की तारीख—(1) नियम 10 या 12 के अधीन उद्गृहीत सुरक्षा शुल्क ऐसा शुल्क अधिरोपित करने वाली अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए अन्तिम, अधिनियम की धारा 8ग की उपधारा (2) के अधीन भी अन्तिम शुल्क उद्गृहीत किया गया है और जहां महानिदेशक ने यह निष्कर्ष अभिलिखित कर दिया है कि वर्धित आयात से घरेलू उद्योग को "बाजार विच्छिन्नता" कारित हुआ

है या कारित होने की आशंका है, वहां उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि ऐसा सुरक्षा शुल्क अनंतिम शुल्क के उद्ग्रहण की तारीख से प्रभावी होगा।

15. शुल्क का प्रतिदाय—यदि अधिनियम की धारा 8ग के अधीन, अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् अधिरोपित सुरक्षा शुल्क, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन पहले से अधिरोपित और संग्रहीत अनंतिम शुल्क से कम है तो आयातकर्ता को उसके अन्तर का प्रतिदाय किया जाएगा।

16. कालावधि—(1) नियम 12 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क समय की केवल ऐसी अवधि के लिए होगा जो "बाजार विच्छिन्नता" को रोकने या उसके उपचार के लिए आवश्यक हो।

(2) इस नियम उपनियम (1) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, नियम 12 के अधीन उद्ग्रहीत शुल्क जब तक कि पहले ही प्रति संहत न कर लिया गया हो, उसके अधिरोपण की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उस वस्तु का, जिस पर ऐसा सुरक्षा शुल्क अधिरोपित किया गया है ऐसी वर्धित मात्राओं में चीम जनवादी गणराज्य से भारत में आयात बना हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" कारित होती है या कारित होने की आशंका है और सुरक्षा शुल्क अधिरोपित रहना चाहिए तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि को बढ़ा सकेगी।

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में ऐसा सुरक्षा शुल्क उस तारीख से, जिसको ऐसा शुल्क पहली बार अधिरोपित किया गया था, दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिरोपित नहीं रहेगा।

17. पुनर्विलोकन—(1) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 8ग के अधीन अधिरोपित सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण को जारी रखे जाने की आवश्यकता का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और यदि उसका, उसे प्राप्त जानकारी के आधार पर, यह समाधान हो जाता है कि,—

- (i) "बाजार विच्छिन्नता" को रोकने या उसके उपचार के लिए ऐसा सुरक्षा शुल्क आवश्यक है तो वह केन्द्रीय सरकार को उस शुल्क का अधिरोपण जारी रखे जाने के लिए सिफारिश करेगा;
- (ii) ऐसे सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण को जारी रखे जाने के लिए कोई औचित्य नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार को उसके प्रत्याहरण के लिए सिफारिश करेगा।

परन्तु जहां ऐसे सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाती है वहां महानिदेशक स्थिति का जो ऐसे अधिरोपण की मध्यावधि से पश्चात् की न हो, पुनर्विलोकन करेगा और यदि समुचित हो तो ऐसे सुरक्षा शुल्क के प्रत्याहरण के लिए या उस शुल्क में फेरफार के लिए सिफारिश करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रारंभ किया गया कोई भी पुनर्विलोकन ऐसे पुनर्विलोकन का प्रारंभ किए जाने की तारीख से ऐसी अवधि के भीतर जो आठ मास से अधिक न हो या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, पूरा कर लिया जाएगा।

(3) नियम 5, 6, 7 और 11 के उपबंध पुनर्विलोकन की दशा में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

उपाबंध

(नियम 8 देखिए)

- (1) अन्वेषण में यह अवधारित करने के लिए कि वर्धित आयात से किसी घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" कारित हुई है या कारित होने की आशंका है, महानिदेशक उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली वस्तु परक और मात्रात्मक प्रकृति के सभी सुसंगत कारकों का, विशिष्टतः संबद्ध वस्तु के आयात में, आत्यंतिक या आपेक्षिक रूप में, वृद्धि की दर और रकम, वर्धित आयात द्वारा लिया गया घरेलू बाजार के अंश, विक्रय, उत्पादन, उत्पादकता, उपयोग क्षमता, लाभ और हानि तथा नियोजन के स्तर में परिवर्तन का, मूल्यांकन करेगा।
- (2) पैरा (1) में निर्दिष्ट अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अन्वेषण वस्तु निष्ठ साक्ष्य के आधार पर संबद्ध वस्तु के वर्धित आयात और "बाजार विच्छिन्नता" या उसकी आशंका के बीच आकस्मिक संबद्धता विद्यमान होने का प्रदर्शन नहीं करता है। जब वर्धित आयात से भिन्न कारक एक ही समय पर घरेलू उद्योग की "बाजार विच्छिन्नता" कारित कर रहे हों तब ऐसी "बाजार विच्छिन्नता" की वर्धित आयात के कारण हुआ नहीं माना जाएगा। ऐसी दशा में, महानिदेशक ऐसी शिकायत को प्रतिपादन या प्रतिशुल्क अन्वेषणों के लिए, जैसा उचित हो प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

[फा. सं. 526/6/2002-सो. शु. (टी. यू.)]

धीरेन्द्र सिंह गब्याल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2002

No. 34/2002-NT-CUSTOMS

G.S.R. 420 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement. - (i) These rules may be called the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002.

(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) "Critical circumstances" means circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause market disruption to the domestic industry and delay in imposition of provisional safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry;

(c) "Increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production;

(d) "Interested Party" includes -

- (i) any exporter or foreign producer or the importer of an article subjected to investigation for purposes of imposition of safeguard duty under section 8C of the Act or a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article;
 - (ii) the government of the People's Republic of China; and
 - (iii) a producer of the like article or directly competitive article in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like article or directly competitive article in India;
- (e) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation under section 8C of the Act;
- (f) "Provisional Duty" means a safeguard duty imposed under sub section (2) of section 8C of the Act;
- (g) all words and expressions used and not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment of Director General (Specific Safeguard). - (1) The Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or such other officer as it may think fit as the Director General (Specific Safeguard) hereinafter referred to as the Director General for the purposes of these rules.

(2) The Central Government may provide to the Director General the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.

4. Duties of the Director General. - Subject to the provisions of these rules, it shall be the duty of the Director General -

- (1) to investigate the existence of "market disruption" or "threat of market disruption" to domestic industry as a consequence of increased import of an article into India;
- (2) to identify the article liable for safeguard duty under section 8C of the Act;
- (3) to submit his findings, provisional or otherwise to the Central Government as to the existence of "market disruption" or "threat of market disruption" to the domestic

industry consequent upon increased import of an article from the People's Republic of China;

(4) to recommend, -

(i) the amount of duty which if levied would be adequate to remove the "market disruption" or "threat of market disruption" to the domestic industry;

(ii) the duration of levy of safeguard duty under section 8C of the Act;

(5) to review the need for continuance of such safeguard duty.

5. Initiation of investigation. - (1) Except as provided in sub-rule (4), the Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like article or directly competitive article, initiate an investigation to determine the existence of "market disruption" or "threat of market disruption" to the domestic industry, caused by the import of an article in such increased quantities, absolute or relative to domestic production.

(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the Director General in this behalf and such application shall be supported by evidence of -

(i) increased imports;

(ii) "market disruption" or "threat of market disruption" to the domestic industry; and

(iii) a causal link between imports and the alleged "market disruption" or "threat of market disruption".

(3) The Director General shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless he examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding-

(a) increased imports;

(b) "market disruption" or "threat of market disruption"; and

(c) a causal link between increased imports and "alleged market disruption" or "threat of market disruption".

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Director General may initiate an investigation *suo motu* if he is satisfied with the information received from any Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as referred to in clause (a), clause (b) and clause (c) of sub-rule (3).

6. Principles Governing Investigations. - (1) The Director General shall, after he has decided to initiate investigation to determine the "market disruption" or "threat of market disruption" to domestic industry, consequent upon the increased import of an article into India, issue a public notice notifying his decision thereto. The public notice shall, *inter alia*, contain adequate information on the following, namely :-

- (i) the article involved;
- (ii) the date of initiation of the investigation;
- (iii) a summary statement of the facts on which the allegation of "market disruption" or "threat of market disruption" is based;
- (iv) reasons for initiation of investigation.
- (v) the address to which representations by interested parties should be directed; and
- (vi) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.

(2) A copy of the public notice shall be forwarded by the Director General to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and other Ministries concerned, known exporters of the article the increased import of which has been alleged to cause or threaten to cause "market disruption" to the domestic industry, the government of the People's Republic of China and other interested parties.

(3) The Director General shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 5 to -

- (i) the known exporters, or the concerned trade association;
- (ii) the government of the People's Republic of China, and
- (iii) the Central Government in the Ministry dealing with Commerce :

Provided that the Director General shall also make available a copy of the application, upon request in writing, to any other interested party.

(4) The Director General may issue a notice calling for any information in such form as may be specified by him from the exporters, foreign producers and government of the People's Republic of China and such information shall be furnished by them in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the Director General may allow on sufficient cause being shown.

Explanation. - For the purpose of this rule the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week after the date on which these documents were sent by the Director General by registered post or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the People's Republic of China.

(5) The Director General shall also provide opportunity to the industrial user of the article under investigation, and to representative consumer organisations in cases where the article is commonly sold at retail level to furnish information which is relevant to the investigation.

(6) The Director General may allow an interested party or its representative to present the information relevant to investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Director General only when it is subsequently submitted in writing.

(7) The Director General shall make available the evidence presented to him by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation.

(8) In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Director General may record his findings on the basis of the facts available to him and make such recommendations to the Central Government as he deems fit under such circumstances.

7. Confidential information. - (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 9 and sub-rule (5) of rule 11, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Director General and shall not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The Director General may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Director General a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, he may disregard such information unless it is demonstrated to his satisfaction from appropriate sources that such information is correct.

8. Determination of "market disruption" or "threat of market disruption". - The Director General shall determine "market disruption" or "threat of market disruption" to the domestic industry taking into account, *inter alia*, the principles laid down in Annexure to these rules.

9. Preliminary findings. - (1) The Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary findings regarding "market disruption" or "threat of market disruption".

(2) The Director General shall issue a public notice regarding his preliminary findings.

(3) The Director General shall send a copy of the public notice to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and in the Ministry dealing with Finance.

10. Levy of provisional duty. - The Central Government may in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 8C of the Act, impose a provisional duty on the basis of the preliminary findings of the Director General :

Provided that such duty shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date on which it was imposed.

11. Final findings. - (1) The Director General shall, within 8 months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, -

- (a) the increased imports of the article under investigation under section 8C of the Act has caused or threatened to cause "market disruption" to the domestic industry; and
- (b) a causal link exists between the increased imports and "market disruption" or "threat of market disruption".

(2) The Director General shall also give his recommendation regarding the amount of duty which, if levied, would be adequate to prevent or remedy "market disruption".

(3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of levy of duty.

(4) The final findings, if affirmative, shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion.

(5) The Director General shall issue a public notice recording his final findings.

(6) The Director General shall send a copy of the public notice regarding his final findings to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and in the Ministry dealing with Finance.

12. Levy of duty. - (1) The Central Government may impose, by a notification in the Official Gazette, upon importation into India of the article covered under the final findings, a safeguard duty under section 8C of the Act not exceeding the amount which has been found adequate to prevent or remedy "market disruption".

(2) If the final finding of the Director General is negative, that is contrary to the *prima facie* evidence on the basis of which the investigation under section 8C of the Act was initiated, the Central Government shall within thirty days of the publication of final findings by the Director General under rule 11, withdraw the provisional duty, if any, imposed under sub-section (2) of section 8C of the Act.

13. Imposition of duty on non-discriminatory basis. - Any safeguard duty under section 8C of the Act imposed under rule 10 or rule 12 shall be on a non-discriminatory basis and applicable to all imports of such article from the People's Republic of China.

14. Date of commencement of duty. - (1) The safeguard duty levied under rule 10 or rule 12 shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette imposing such duty.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a provisional duty under sub-section (2) of section 8C of the Act has been levied and where the Director General has recorded a finding that increased imports have caused or threaten to cause "market disruption" to domestic industry, it shall be specified in the notification under sub-rule (1) that such safeguard duty shall take effect from the date of levy of the provisional duty.

15. Refund of duty. - If the safeguard duty imposed after conclusion of the investigation under section 8C of the Act is lower than the provisional duty under sub-section (2) of that section already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.

16. Duration. - (1) The duty levied under rule 12 shall be only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy "market disruption".

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of this rule, the duty levied under rule 12 shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of its imposition :

Provided that if the Central Government is of the opinion that the article on which such safeguard duty is imposed continues to be imported into India, from People's Republic of China, in such increased quantities so as to cause or threatening to cause "market disruption" to domestic industry and the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition :

Provided further that in no case such safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.

17. Review. - (1) The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty imposed under section 8C of the Act and shall, if he is satisfied on the basis of information received by him that -

- (i) such safeguard duty is necessary to prevent or remedy "market disruption", recommend to the Central Government for the continued imposition of that duty ;
- (ii) there is no justification for the continued imposition of such safeguard duty, recommend to the Central Government for its withdrawal :

Provided that where the period of imposition of such safeguard duty exceeds three years, the Director General shall review the situation not later than the mid-term of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard duty or for the variation of that duty.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding 8 months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.

(3) The provisions of rules 5,6,7 and 11 shall *mutatis mutandis* apply in the case of review.

ANNEXURE

(See rule 8)

(1) In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause "market disruption" to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.

(2) The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and "market disruption" or threat thereof. When factors other than increased imports are causing "market disruption" to the domestic industry at the same time, such "market disruption" shall not be attributed to increased imports. In such case, the Director General may refer the complaint to the authority for anti-dumping or countervailing duty investigations, as appropriate.

[F. No. 526/6/2002-CUS(T.U.)]

DHIRENDRA SINGH GARBYAL, Under Secy.

